



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092020-221604  
CG-DL-E-08092020-221604

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]  
No. 234]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2020/भाद्र 17, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2020/BHADRA 17, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

(द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2020

मामला सं. (एस जी) 06/2020

**विषय :** भारत जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 के अंतर्गत जापान से भारत में “पीवीसी सस्पेंशन ग्रेड रेजिन” के आयातों के संबंध में द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की शुरुआत की सूचना।

**फा. सं. 20/6/2020-डीजीटीआर.**—यतः यह आवेदन भारत जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 (जिसे उक्त नियमावली भी कहा गया है) के अंतर्गत मैसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, मै. डीसीएम श्रीराम लिमिटेड तथा मै. कैम्प्लास्ट कुडालोर विनायल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है जिसमें जापान (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से पीवीसी सस्पेंशन ग्रेड रेजिन (जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद, या पीयूसी या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के बढ़ते हुए आयातों और भारत में समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद के घरेलू उत्पादक को गंभीर क्षति होने का आरोप लगाया गया है।

**विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी):**

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “विनायल क्लोराइड मोनोमर का होमो-पॉलीमर (सस्पेंशन ग्रेड) जिसमें विभिन्न पॉलीमर श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं तथा जो सीमाशुल्क वर्गीकरण सं. 3904 के अंतर्गत आता” है। विचाराधीन उत्पाद में पीवीसी सस्पेंशन रेजिन जैसे क्रॉस लिंकड पीवीवी, क्लोरीनेटेड पीवीवी (सीपीवीसी) विनायल क्लोराइड-विनायल एसीटेट कोपालीमर (वीसी-वीएसी), पीवीसी पेस्ट रेजिन तथा पीवीसी ब्लेंडिंग रेजिन शामिल नहीं हैं। विचाराधीन उत्पाद को वर्तमान अधिसूचना में “पॉली विनायल क्लोराइड (पीवीसी) रेजिन”, “सस्पेंशन ग्रेड” अथवा पीवीसी सस्पेंशन रेजिन अथवा “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है।

**समान वस्तु**

3. आवेदक ने दावा किया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु से तुलनीय है। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।

**घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

4. वर्तमान याचिका मैसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, मैसर्स डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और मैसर्स चेम्पलास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड द्वारा दायर की गई है, जिनके उत्पादन का भारतीय उत्पादन में एक बड़ा अनुपात है। आवेदकों के अलावा, भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड विषय वस्तुओं के दो अन्य उत्पादक हैं जिन्होंने इस याचिका का विरोध नहीं किया है।
5. याचिकाकर्ता कंपनियाँ भारतीय उत्पादन का 25% से अधिक हिस्सा बनाती हैं और भारतीय उत्पादन में एक बड़ा अनुपात बनाती हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि, इस तरह के उत्पाद के किसी अन्य घरेलू निर्माता द्वारा व्यक्त किए गए आवेदन का कोई विरोध नहीं है, प्राधिकरण ने नियमों के नियम 2 (ग) के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता कंपनियों को घरेलू उद्योग माना है। याचिकाकर्ता कंपनियों को इसके बाद घरेलू उद्योग या डीआई के रूप में संदर्भित किया जाता है।

**जांच की अवधि**

6. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचारित अवधि अप्रैल, 2016 से मार्च, 2020 तक की है।

**संबद्ध देश**

7. वर्तमान जांच में शामिल देश जापान है।

**बढ़े हुए आयात**

8. आवेदकों ने दावा किया है कि जापान से विचाराधीन उत्पाद का आयात, क्रमोत्तर आयात शुल्क कटौती शुरू होने से पहले काफी कम था वह अब निरपेक्ष रूप से और उत्पादन और खपत के संबंध में काफी बढ़ गया है। यह ध्यान दिया जाता है कि पीओआई के दौरान पीयूसी के आयात में वृद्धि महत्वपूर्ण है और अगस्त, 2011 से टैरिफ कटौती की शुरुआत के बाद बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है। विषय वस्तुओं के आयात में वृद्धि की दर को महत्वपूर्ण माना जाता है। अवधि, क्वॉंटम, भारत में कुल आयात और खपत।

**घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति:**

9. आवेदकों ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों के कारण उन्हें गंभीर क्षति हुई है आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओआई में गिरावट आई है।
10. आवेदकों ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों में भारी वृद्धि के मद्देनजर द्विपक्षीय रक्षोपाय तत्काल लागू करने का अनुरोध किया है।

11. प्राधिकारी पाते हैं कि इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारी वृद्धि हुई है जिससे भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है और संबद्ध देश से बड़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।

### जांच की शुरुआत

12. यह निर्धारित करने के बाद कि रक्षोपाय जांच की शुरुआत करने के लिए औचित्य ठहराने हेतु प्रथमदृष्टया साक्ष्य है, महानिदेशक इस जांच की शुरुआत करना उचित समझते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या जापान से विचाराधीन उत्पाद के आयात बड़े हुए आयात हैं और क्या बड़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या उसका खतरा है।
13. सभी हितबद्ध पक्षकार इस नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत करा सकते हैं :

महानिदेशक  
व्यापार उपचार महानिदेशालय  
जीवन तारा बिल्डिंग,  
चतुर्थ तल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

14. COVID-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, सभी संचारों को नामित प्राधिकारी को ईमेल पते [adg11-dgtr@gov.in](mailto:adg11-dgtr@gov.in) पर ईमेल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए; और [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in), [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in); [ad11-dgtr@gov.in](mailto:ad11-dgtr@gov.in) पर कॉपी करें।
15. सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को अलग से लिखा जा रहा है।
16. कोई अन्य पक्षकार जो इस जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में समझे जाने का इच्छुक है, वह इस नोटिस की तिथि से 30 दिनों के भीतर पूर्वाक्त पते पर महानिदेशक को अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
17. यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है जो महानिदेशक रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। सूचना हार्ड प्रतियों और सॉफ्ट प्रतियों में उपलब्ध की जानी चाहिए।
18. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना - प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीयता के मामले में उसके दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येकपृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को महानिदेशक द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और महानिदेशक अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रत्येक के दो-दो (2) सैट में हार्ड कॉपियों के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है। अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और महानिदेशक की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद महानिदेशक गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने के लिए पृष्ठ 4 के 4 का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं। सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित

कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को महानिदेशक द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद महानिदेशक ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

19. कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।
20. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो महानिदेशक अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बिद्युत बिहारी स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

### INITIATION-NOTIFICATION

(Bilateral Safeguard Investigation)

New Delhi, the 8th September, 2020

Case No-(SG) 6/2020

**Subject: Notice of initiation of Bilateral Safeguard Investigation concerning imports of “PVC Suspension Grade Resin” into India from Japan under India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017.**

**F. No. 20/6/2020-DGTR.**—Whereas, an application has been filed under India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter also referred to as the “said Rules”) by M/s DCW Limited, M/s DCM Shriram Limited and M/s Chemplast Cuddalore Vinyls Limited (herein after referred alleging increased imports of “PVC Suspension Grade Resin” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC” or subject goods) from Japan (also referred to as subject country) causing serious injury to the domestic producer of like or directly competitive product in India.

#### Product under Consideration (PUC)

2. The product under consideration in the present investigation is “homo-polymer of vinyl chloride monomer (suspension grade), where various polymer chains are not linked to each other, falling under Customs Classification No. 3904”. The product under consideration excludes PVC suspension resins such as cross-linked PVC, chlorinated PVC (CPVC), vinyl chloride – vinyl acetate copolymer (VC-VAc), PVC paste resin and PVC blending resin. The product under consideration has been also referred to as “Poly Vinyl Chloride (PVC) Resin”, “Suspension Grade” or “PVC Suspension Resin” or “the subject goods” in the present notification.

#### Like Article

3. Applicants have claimed that there is no known difference in the product produced by the petitioners and exported from the subject countries. Subject goods produced by the domestic industry are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods with the subject goods imported from the subject countries. The consumers are using the two interchangeably.

#### Domestic Industry and Standing

4. The present petition has been filed by M/s DCW Limited, M/s DCM Shriram Ltd. and M/s Chemplast Cuddalore Vinyls Limited whose production constitutes a major proportion in the Indian production.

Apart from the applicants, there are two other producers of the subject goods in India namely Reliance Industries Limited and Finolex Industries Limited who have not opposed this petition.

5. The petitioning companies together constitute more than 25% of the Indian production and constitute a major proportion in the Indian production. Keeping in view that, there is no opposition to the application expressed by any other domestic producer of the like product, the Authority has considered the petitioner companies as the domestic industry within the meaning of Rule 2(c) of the Rules. The petitioner companies are hereinafter referred to as Domestic Industry or DI

#### **Period of Investigation**

6. The period considered for the purpose of the present investigation is April, 2016 to March, 2020.

#### **Subject country**

7. The country involved in the present investigation is Japan.

#### **Increased Imports**

8. The Applicants have claimed that imports of the product under consideration from Japan were quite low before the commencement of duty reduction and have increased in absolute terms and in relation to production and consumption. It is noted that the increase in imports of PUC is significant during the POI and is continuing the increasing trend witnessed post the commencement of the tariff reduction with effect from August, 2011. The rate of increase in imports of subject goods is considered significant considering the duration, the quantum, the total imports and the consumption in India.

#### **Serious Injury to the domestic industry**

9. The Applicants have claimed that the increased imports of the product under consideration have caused serious injury to it. The applicants claimed that the market share of the DI has declined whereas market share of subject imports has increased. They have also claimed that their profits, cash profits, PBIT and ROI have declined.
10. The Applicants has requested for immediate imposition of bilateral safeguard measure in view of significant increase in imports of subject goods from subject country.
11. The Authority finds that there is prima facie evidence that imports of product under consideration have increased significantly causing serious injury to the DI of the like article in India and there is causal link between increased imports from subject country and the serious injury caused to the DI.

#### **Initiation**

12. After determining that there is prima facie evidence to justify initiation of the safeguard investigation, the Director-General considers appropriate to initiate the investigation in order to determine whether the imports of the product under consideration from Japan constitute increased imports and whether the increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to the DI.
13. All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice to:

Director General  
Directorate General of Trade Remedies  
Jeevan Tara Building,  
4th Floor 5, Parliament Street, New Delhi -110001

14. In view of the special circumstances arising out of the COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg11-dgtr@gov.in](mailto:adg11-dgtr@gov.in); and copy to [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in); [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in); [ad11-dgtr@gov.in](mailto:ad11-dgtr@gov.in)
15. All known interested parties are also being addressed separately.
16. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director-General on the aforementioned address within 30 days from the date of this notice.



17. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Director-General may record its findings on the basis of the facts available on record. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.
18. Submission of Information on Confidential Basis – The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Director-General and the Director-General shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Director General. The Director-General may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Director General is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or Page 4 of 4 to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. Any submission made without a meaningful non- confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Director-General. The Director-General, on being satisfied and accepting the need for keeping the information provided as confidential shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.
19. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.
20. In case, where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Director-General may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Special Secy. & Designated Authority